



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 25, 2008/चैत्र 5, 1930

No. 102]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 25, 2008/CHAITRA 5, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

प्रारंभिक अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2008

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित ग्रैफाइट इलैक्ट्रोडस पर पाटनरोधी शुल्क आरोपित किये जाने के संबंध में निर्णायक समीक्षा शुरू करना ।

सं. 15/7/2007-डीजीएडी.—निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (क्षति निर्धारण करने के लिए पाटित वस्तुओं को ज्ञात करना, शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन) नियमावली 1995 को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 9-4-2003 की अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं. 28/1/2001-डीजीएडी द्वारा चीन जनवादी गणराज्य से सामान्य पावर ग्रेड ग्रैफाइट इलैक्ट्रोडस से संबंधित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने को जारी रखने की सिफारिश की है तथा दिनांक 7-7-2003 की अधिसूचना सं. 101/2003-सीमा शुल्क द्वारा केंद्र सरकार ने निर्णायक पाटनरोधी शुल्क लगाया है ।

2. समीक्षा और प्रारंभिक जांच के लिए आधार

वर्तमान याचिका मै. ग्रैफाइट इंडिया लि., कोलकाता और एचईजी लि., जिला रायसन, मध्य प्रदेश (जिसे बाद में आवेदक कहा गया है) द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई है । आवेदक द्वारा यह दावा किया गया है कि देश में संबंधित वस्तुओं के कुल उत्पादन में 100% प्रतिनिधित्व है क्योंकि भारत में संबद्ध वस्तुओं का वे एकमात्र उत्पादक हैं और भारत में उस वस्तु का कोई दूसरा उत्पादक नहीं है । चेतावनी पत्र के जवाब में, आवेदक ने चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं पर आरोपित पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए समीक्षा जांच शुरू करने के लिए याचिका दायर की है । अपने आवेदन में, याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि प्रारंभ में जिस स्रोत पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था, से पाटन खत्म नहीं हुआ है तथा पाटनरोधी शुल्क लगे रहने के बाद भी घरेलू उद्योग को क्षति हुई है । आगे यह भी दावा किया गया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु पर आरोपित पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने से पाटन पर और गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है क्योंकि घरेलू उद्योग को निर्यातकों द्वारा दी गई कीमतों के समतुल्य रखने को विवश होना पड़ेगा । ऊपर उल्लिखित अधिसूचनाओं के तहत और 5 वर्षों की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं पर आरोपित पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का अनुरोध किया है ।

याचिका की जांच के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी समझते हैं कि रहने पर पाटन तथा पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क को हटाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के दावे को जांच के लिए यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों के तहत इस चरण पर आरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करना उपयुक्त होगा ।

3. विचाराधीन उत्पाद

इस निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पादन 24" सहित 8" तक के व्यास वाले विभिन्न हाई पावर ग्रेड (एचपीजी) इलैक्ट्रोड सहित नार्मल पावर ग्रेड (एनपीजी) ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड हैं।

चूँकि वर्तमान जांच निर्णायक समीक्षा है, विचाराधीन उत्पादन वही है जैसा कि मूल जांच में परिभाषित किया गया है, क्योंकि उसके बाद की अवधि में कोई महत्वपूर्ण घटना अथवा परिवर्तन नहीं हुआ है।

4. शामिल देश

वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य है (जिसे बाद में संबद्ध देश कहा गया है)।

5. प्रक्रिया

दिनांक 9-4-2003 की अधिसूचना सं. 28/1/2001-डीजीएडी द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों पर तथा दिनांक 7-7-2003 की अधिसूचना सं. 101/2003-सीमाशुल्क द्वारा आरोपित अंतिम शुल्क की समीक्षा का निर्णय लेते हुए, प्राधिकारी यहां यह समीक्षा करने के लिए जांच शुरू करते हैं कि सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं को अभिज्ञात करना, पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण एवं क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार तथा क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने से फिर से पाटन की समस्या उत्पन्न होगी तथा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात से क्षति बढ़ेगी। इस समीक्षा में दिनांक 9-4-2003 की अधिसूचना सं. 28/1/2001-डीजीएडी की सभी पहलुएं (मूल जांच का अंतिम निष्कर्ष) शामिल हैं। प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के अनुरूप पैराग्राफ 2 में उल्लिखित आवेदक को घरेलू उपयोग के रूप में विचार करने का प्रस्ताव करता है क्योंकि यह भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन का प्रमुख भाग है।

नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य की स्थापना करने के उद्देश्य ब्राजील को तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में चुनने के लिए उपर्युक्त परिकल्पना है।

6. जांच अवधि

वर्तमान समीक्षा के प्रयोनार्थ जांच अवधि (पीओआई) 1-10-2006 से 30-09-2007 (12 महीने) है। हालाँकि क्षति जांच की अवधि में जांच अवधि तथा जांच अवधि से पहले के तीन वर्ष अर्थात् अप्रैल 2004, मार्च 2005, अप्रैल 2005, मार्च 2006 और अप्रैल 2006, मार्च 2007 है।

7. सूचना देना

संबद्ध देश के निर्यातकों को भारत में उनके दूतावास के जरिए उनके सरकार को तथा इस जांच से संबंधित भारत में ज्ञात आयातकों को निर्धारित प्रपत्र एवं तरीका से संबंधित सूचना देने के लिए तथा नीचे लिखे पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को अपना दृष्टिकोण देने के लिए अलग से लिखा जा रहा है।

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग, भारत सरकार
कमरा सं. 240,
नई दिल्ली-110011

ऊपर नियमावली के नियम 6(5) के अनुसार, जांचाधीन वस्तु के औद्योगिक उपभोक्ता को तथा उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों को जो पाटन, क्षति और दुर्घटना के संबंध में जांच से संबंधित सूचना दे सकता है को अवसर भी प्रदान कर रहा है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार नीचे तय की गई समय-सीमा के अंदर दे सकती है।

8. समय-सीमा

(क) सामान्य समय सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित सूचना को लिखित रूप में ऐसे भेजा जाना चाहिए कि वह इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि के 40 (चालीस) दिनों के अंदर ऊपर उल्लिखित पता पर प्राधिकारी के पास पहुँच जाए। तथापि, ज्ञात निर्यातकों एवं आयातकों को जिन्हें अलग से प्रेषित किया जा रहा है, को अपनी सूचना उनको लिखी गई पत्र की तारीख से चालीस दिन के अंदर अलग से भेजना होगा।

(ख) बाजार अर्थव्यवस्था देश के चुनाव के लिए विशिष्ट समय-सीमा

हितबद्ध पक्षकार इस प्रारंभिक अधिसूचना के पैरा 5 में यथाउल्लिखित चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य की स्थापना के उद्देश्य से बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में परिकल्पित ब्राजील के उपर्युक्तता पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। इन टिप्पणियों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 4 सप्ताहों के अंदर अवश्य ही भेज देना चाहिए।

9. सार्वजनिक फाइल की जांच

नियमावली 6(7) के रूप में, निर्दिष्ट प्राधिकारी सार्वजनिक फाइल का रख-रखाव करते हैं। कोई हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के गैर गोपनीय अंश से संबंधित सार्वजनिक फाइल की जांच कर सकते हैं। हितबद्ध पक्षकार द्वारा फाइल देने पर मना करने

की स्थिति में अथवा अन्यथा उचित समय अवधि में आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर अथवा जांच को महत्वपूर्ण रूप से रोकने पर निर्दिष्ट प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष का रिकार्ड कर सकती है तथा जैसा कि उपयुक्त हो ऐसी सिफारिशें केंद्र सरकार से कर सकती है।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2008

(SUNSET REVIEW)

Subject : Initiation of Sunset Review regarding anti-dumping duty imposed on Graphite Electrodes originating in or exported from China-PR.

No. 15/7/2007-DGAD.—The Designated Authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended in 1995, and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, recommended continued imposition of anti-dumping duty concerning imports of Normal Power Grade Graphite Electrodes from China-PR. *vide* Final Finding Notification No. 28/1/2001-DGAD dated 9-4-2003 and definitive Anti-Dumping duty was imposed by the Central Government *vide* Notification No. 101/2003 Customs dated 7-7-2003.

2. Grounds for review and initiation

The present application has jointly been filed by M/s. Graphite India Limited Kolkata and HEG Limited Distt. Raisen M.P. (hereinafter referred to as applicants). It has been claimed by the applicants that they represent 100% of the total production of subject goods in the country as they are the sole producers of the subject goods in India and there are no other producers of the same in India. As a response to the alert letter, the applicants have filed an application for carrying out review investigations for continuation of the anti-dumping duty imposed on the subject goods originating in or exported from China-PR. In their application, the petitioners have claimed that dumping has not ceased to exist from any of the sources on which anti-dumping duties were imposed initially and injury to the domestic industry continues despite anti-dumping duties being in place. It has further been claimed that cessation of anti-dumping duties imposed on subject goods from subject country is likely to have a more serious impact of dumping as domestic industry will be forced to match the prices offered by the exporters and have requested for continuation of the anti-dumping duty imposed on subject goods under the above mentioned notifications for a further period of 5 years.

On the basis of examination of the application, the Designated Authority considers that the sunset review of the anti-dumping duty imposed would be appropriate at this stage under the provision of Section 9A of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 as amended to investigate the claim of the applicant about continued dumping and consequential injury to the Domestic Industry in case of cessation of Anti-dumping Duty, already in place.

3. Product under Consideration

The product under consideration in this sunset review is "Normal Power Grade (NPG) Graphite Electrodes including its variant High Power Grade (HPG) Electrodes of diameters from 8" up to and including 24".

Since, the present investigation is a review investigation; product under consideration remains the same as has been defined in the original investigation, as there has been no significant development or change in the product during the period thereafter.

4. Countries Involved

The country involved in the present investigations is China PR (also referred to as subject country hereinafter).

5. Procedure

Having decided to review the final findings issued *vide* Notification No. 28/1/2001-DGAD dated 9-4-2003 and final duty imposed by Notification No. 101/2003 Customs dated 7-7-2003, the Authority hereby initiates investigations to review whether cessation of anti-dumping duty is likely to lead to recurrence of dumping and injury on imports of subject goods originating in or exported from subject country, in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment & Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995. The review covers all aspects of Notification 28/1/2001-DGAD dated 9-4-2003

(Final findings of the original investigations). The Authority proposes to consider applicant as mentioned in paragraph 2 as domestic industry in accordance with the Rules supra as it constitutes the major proportion of the production of the subject goods in India.

In accordance with Para 7 to Annexure-1 of the Rules, it is envisaged to choose Brazil as an appropriate market economy third country for the purpose of establishing normal value in respect of the People's Republic of China.

6. Period on Investigation

The period of investigation (POI) for the purpose of the present review is from 1-10-2006 to 30-09-2007 (12 months). The period of injury examination would however include POI and three years prior to the POI i.e. April 2004—March 2005, April 2005—March 2006 and April 2006—March 2007.

7. Submission for information

The exporters in the subject country, their Government through their Embassy in India and importers in India known to be concerned with this investigation are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority at the following address:

Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, Government of India, Room No. 240, Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

As per Rule 6(5) of Rule supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the article under investigation, and to representative consumer organizations who can furnish information which is relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

8. Time Limit

(a) General Time Limits

Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty (40) days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within forty (40) days from the date of the letter addressed to them separately.

(b) Specific time limit for selection of market economy country

Interested parties to the investigation may wish to comment on the appropriateness of Brazil, which, as mentioned in the Para 5 of this initiation notification, envisaged as a market economy country for the purpose of establishing normal value in respect of the China-PR. These comments must be submitted within four (4) weeks from the date of publication of this notification.

9. Inspection of Public File

In terms of Rule 6 (7), Designated Authority maintains a public file. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Designated Authority may record findings on the basis of facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority